राष्ट्रीय हिन्दी मेल, भोपा
12 FEB 2014

कृषि कर्मण पुरस्कार : बधाई

कृषि के क्षेत्र में विकास दर 15 तक प्राप्त कर मध्यप्रदेश में लगातार दूसरे वर्ष उल्लेखनीय प्रगति की है। कृषि कर्मण पुरस्कार इस बार भी मध्यप्रदेश को मिला। शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री के नाते हमेशा कहते रहे हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाना उनकी सरकार का उद्देश्य है। यह अच्छी बात है कि मध्यप्रदेश देश के उन कृषि प्रधान राज्यों जिनका उत्पादन सर्वाधिक होता है की श्रेणी में आ गया है। गेहूं के उत्पादन में मध्यप्रदेश यदि इसी तरह प्रगति करता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब वह पंजाब को पीछे छोड़ देगा। किसान के बेटे के रूप में अपने को जनता के बीच ले जाने वाले मुख्यमंत्री किसान की पीड़ा को भलीभांति समझते हैं। किसान खेत में कितनी ही मेहनत करे, अच्छी फसल बो ले और वर्षा कम हो जाए तो कर्ज में डूबा किसान अंततः और गरीबी में पहुंच जाता है। एक तरफ कर्ज और दूसरी तरफ गरीबी उसको आत्महत्या के लिए मजबूत कर देती है। ऐसे किस्से महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश से आते रहे हैं और कुछेक मामले मध्यप्रदेश में भी कहे जा सकते हैं। इसी पीड़ा और दर्द को यदि कोई सरकार अपने लिए चुनौती मान ले और उस चुनौती को पार करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाए तो कोई कारण नहीं कि सफलता न मिले। मुख्यमंत्री बनते समय ही शिवराजसिंह चौहान ने सबसे पहले किसानों को कम ब्याज पर ऋण और अब तो बिना ब्याज के कर्ज देना शुरू किया है। इससे एक लाभ यह हुआ कि ब्याज की वजह से किसान पर कर्ज नहीं बढ़ा और फसल यदि हल्की पतली हो भी जाए तो वह उससे उबर आता है। दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया, जहां पानी की उपलब्धता थी वहां किसानों को बिजली के दर में सहुलियत दी और जहां पानी नहीं था वहां कुएं और खेत-तालाब योजना के जरिये किसानों को सिंचित खेती के लिए प्रेरित किया। 10 साल पहले जब भाजपा सरकार में नहीं थी तब और अब में सिंचित खेती के रकबे में 10 गुना वृद्धि हुई है। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसको भले ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार न मिला हो, पर इसको रेखांकित नहीं किया जाना सरकार के साथ नाइंसाफी होगी। लगातार दो बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिलने के बाद अब मीडिया का और मध्यप्रदेश के बाहर के लोगों का ध्यान भी गया है। सार्वजनिक रूप से इस बात का जिक्र होने लगा है कि कल तक बीमारू राज्य कहा जाने वाला मध्यप्रदेश आज उससे बाहर निकल गया है और यही विकास की गति रही तो एक दिन अव्वल राज्यों में गिना जाएगा। अभी-अभी नर्मदा और क्षिप्रा के मिलन के बाद चार नदियों को जोड़ने की जो बात उन्होंने की है उससे खेत के सूखे कंठ न केवल तरल होंगे, बल्कि कृषि उत्पादन बढ़ेगा और इससे प्रदेश को भारी कृषि उत्पादक राज्य की श्रेणी में आने का अवसर मिलेगा, बल्कि किसान भी समृद्ध होंगे। कृषि उत्पादन से जुड़े छोटे-मोटे समानांतर उद्योग भी पनपेंगे और हो सकता है कि कृषि के काम में आने वाले उपकरण और खाद, कारखानों का मध्यप्रदेश में आने का रास्ता साफ होगा। खेत और किसान दोनों यदि आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी यह इस बात के संकेत है। कुल मिलाकर सरकार और शासन के प्रयासों को मिली सफलता के लिए उनकी पीठ तो थपथपाई जा सकती है। आलोचना को जहां स्थान हो वहां प्रशंसा में कंजूसी अच्छी बात नहीं है।